

प्रारंभिक परीक्षा

डिजिटल पहुंच मौलिक अधिकार का हिस्सा है - सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

हाल ही में दिए गए एक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश -

- डिजिटल पहुंच एक अधिकार के रूप में:
 - कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच के लिए डिजिटल सेवाएँ आवश्यक हैं।
 - इसलिए, पहुंच अब वैकल्पिक नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व बन गई है।
 - डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्यायसंगत दोनों होना चाहिए।
- KYC नियमों में संशोधन: आरबीआई और अन्य वित्तीय नियामकों को चाहिए कि वे:
 - चेहरे की पहचान और पलक झपकाने के विकल्प प्रदान करें और ओटीपी-आधारित या वीडियो-आधारित सत्यापन विधियों की अनुमति दें।
 - चेहरे की विकृति (एसिड हमलों के कारण) या दृश्य हानि वाले व्यक्तियों को बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाएं।
- परीक्षण में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी:
 - सभी विनियमित डिजिटल संस्थाओं (ऐप्स, वेबसाइट) को नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं के साथ प्री-लॉन्च परीक्षण करना होगा।
 - सार्वजनिक रोलआउट से पहले ऐप्स को सुलभ के रूप में प्रमाणित करें।
- अनिवार्य पहुंच मानक: वेबसाइट, मोबाइल ऐप और नागरिक प्लेटफॉर्म को:
 - भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) पहुंच मानदंडों का पालन करना चाहिए और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 46 का अनुपालन करना चाहिए।
- नोडल एक्सेसिबिलिटी अधिकारियों की नियुक्ति: सभी विनियमित संस्थाओं (सरकारी और निजी) को
 - डिजिटल पहुंच के लिए समर्पित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।
 - पहुंच संबंधी चिंताओं के लिए विशिष्ट शिकायत निवारण तंत्र बनाना चाहिए।

कानूनी आधार और संवैधानिक अनुच्छेद लागू किए गए -

- अनुच्छेद 21: जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में अब डिजिटल पहुंच भी शामिल है।
- अनुच्छेद 14 और 15: समानता और भेदभाव न करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 38: डिजिटल समावेशन सहित लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निर्देश।
- दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016:
 - धारा 46: इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों में पहुंच को अनिवार्य बनाता है।

स्रोत: [The Hindu - Digital access FR](#)

प्रोजेक्ट सीक्योर (Project SeaCURE)

संदर्भ

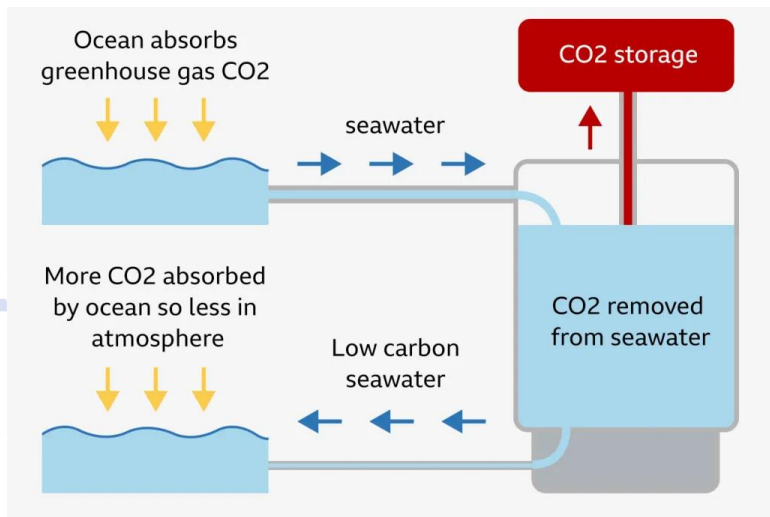
ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में समुद्री जल से कार्बन निकालने के लिए इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर एक पायलट परियोजना शुरू की है।

प्रोजेक्ट सीक्योर के बारे में -

- यह समुद्री जल से सीधे कार्बन निकालने के लिए एक पायलट परियोजना है जो वायुमंडलीय CO₂ के स्तर को कम करने के लिए एक लागत प्रभावी और स्केलेबल समाधान प्रदान कर सकती है।
- पारंपरिक कार्बन कैप्चर तकनीकों के विपरीत जो उत्सर्जन को उनके स्रोत या हवा से कैप्चर करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, सीक्योर महासागर को लक्षित करता है, जो वायुमंडल की तुलना में 150 गुना अधिक कार्बन रखता है।

सीक्योर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है -

- समुद्री जल का ग्रहण:** इंग्लिश चैनल के नीचे एक पाइप समुद्री जल को फेसिलिटी में खींचता है।
- अम्लीकरण प्रक्रिया:** समुद्री जल को अधिक अम्लीय बनाने के लिए उपचारित किया जाता है।
 - इसके कारण घुला हुआ अकार्बनिक कार्बन, गैसीय CO₂ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ खोलने पर गैस निकलती है।

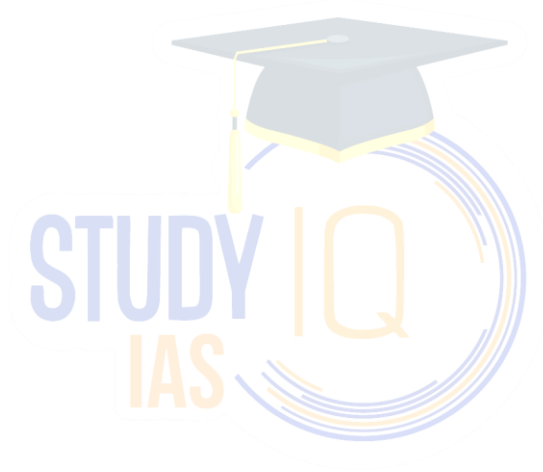


- CO₂ स्ट्रिपिंग:** अम्लीय जल को एक बड़े स्टेनलेस स्टील टैंक (जिसे "समुद्री जल स्ट्रिपर" कहा जाता है) से गुजारा जाता है, जो वायु संपर्क को अधिकतम करता है।
 - CO₂ को हवा में छोड़ा जाता है और फिर सोख लिया जाता है और कैप्चर कर लिया जाता है।
- CO₂ कैप्चर:** उत्सर्जित CO₂ को जले हुए नारियल के छिलकों (एक प्राकृतिक सोर्बेंट) का उपयोग करके अवशोषित किया जाता है, फिर सांद्रित किया जाता है और संग्रहीत किया जाता है।
- जल निष्प्रभावीकरण एवं वापसी:** जल की अम्लीयता को निष्प्रभावित करने के लिए क्षार मिलाया जाता है।
 - कम कार्बन वाले पानी को समुद्र में बहने वाली एक धारा में पम्प कर दिया जाता है।
 - एक बार समुद्र में वापस आने पर यह पानी वायुमंडल से अधिक CO₂ को पुनः अवशोषित कर लेता है।

संभावित पर्यावरणीय प्रभाव -

- फाइटोप्लांकटन और मसल्स जैसे समुद्री जीव कार्बन पर निर्भर करते हैं।
- मसल्स इसका उपयोग खोल बनाने के लिए करते हैं; फाइटोप्लांकटन इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं।
- समुद्री जल में कार्बन के स्तर में परिवर्तन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है।

स्रोत: [BBC](#) - [SeaCURE](#)



हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (Green Hydrogen Certification Scheme)

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) शुरू की है।

हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के बारे में -

- इस योजना का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन (GH) उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए एक ढांचा स्थापित करना तथा पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और बाजार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।
- इसे यह प्रमाणित करने के लिए लॉन्च किया गया है कि उत्पादित हाइड्रोजन वास्तव में हरित है, अर्थात् कम उत्सर्जन वाले नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित है।
- इससे ग्रीनवाशिंग (हरित उत्पादन के झूठे दावे) को रोका जा सकेगा तथा भारत के हरित हाइड्रोजन निर्यात में वैश्विक विश्वास का निर्माण होगा।
- नोडल एजेंसी:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)
- हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं के लिए दो प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे:
 - संकल्पना प्रमाणपत्र (स्वैच्छिक)
 - सुविधा स्तर प्रमाणपत्र (अनिवार्य)।
- हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए GHG उत्सर्जन तीव्रता की गणना MNRE हरित हाइड्रोजन उत्सर्जन गणना पद्धति का पालन करेगी।
- प्रमाणपत्र गैर-हस्तांतरणीय या व्यापार योग्य है और किसी भी उत्सर्जन में कमी क्रेडिट के लिए दावा नहीं किया जा सकता है।

हरित हाइड्रोजन की परिभाषा (भारतीय मानक के अनुसार) -

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अनुसार:
 - हरित हाइड्रोजन को उत्पादित हाइड्रोजन के प्रति किलोग्राम के लिए 2 किलोग्राम से कम CO₂ उत्सर्जित करना चाहिए।
 - इसे निम्न का उपयोग करके उत्पन्न किया जाना चाहिए:
 - नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जल) द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस।
 - बायोमास आधारित विधियाँ (गैर-जीवाश्म)।

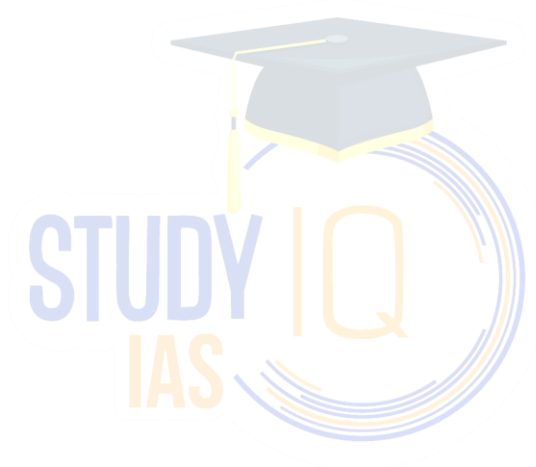
हरित हाइड्रोजन मिशन -

- इसे 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- नोडल मंत्रालय:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
- योजना कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए):** राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई)।
- मुख्य उद्देश्य:**
 - 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना।
 - जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करना।

GREEN
Hydrogen produced by electrolysis of water, using electricity from renewable sources like hydropower, wind, and solar. Zero carbon emissions are produced.
PINK/PURPLE/RED
Hydrogen produced by electrolysis using nuclear power.
TURQUOISE
Hydrogen produced by the thermal splitting of methane (methane pyrolysis). Instead of CO ₂ , solid carbon is produced.
BLACK/GRAY
Hydrogen extracted from natural gas using steam-methane reforming.
BLUE
Grey or brown hydrogen with its CO ₂ sequestered or repurposed.
BROWN
Hydrogen extracted from fossil fuels, usually coal, using gasification.

- हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न (जैसे हरित अमोनिया) के निर्यात को बढ़ावा देना।
- इस्पात, उर्वरक, शोधन, शिपिंग और भारी परिवहन जैसे क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करना।
- **प्रमुख घटक:**
 - **SIGHT कार्यक्रम:** इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित करते हुए दो अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र प्रदान किए जाएंगे।
 - **रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार साझेदारी (SHIP):** मिशन के तहत अनुसंधान एवं विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढांचे को सुगम बनाया जाएगा।
- **निर्यात केंद्र:** निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, तीन अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में चुना गया है:
 - कांडला (गुजरात), पारादीप (ओडिशा) और तूतीकोरिन (तमिलनाडु)।

स्रोत: [Indian Express - Green Hydrogen](#)



समाचार संक्षेप में

लक्कुंडी मंदिर

- कर्नाटक के लक्कुंडी मंदिरों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने की तैयारी है।

लक्कुंडी मंदिर के बारे में -

- ये कर्नाटक के गडग जिले में स्थित हैं।
- इन मंदिरों का निर्माण पश्चिमी चालुक्यों के काल में हुआ था।
- पूरे गांव में लगभग 50 प्राचीन मंदिर फैले हुए हैं। साथ ही 101 सीढ़ीदार कुएं भी हैं, जिन्हें **कल्याणी** कहा जाता है।
 - कासी विश्वनाथ मंदिर सबसे अलंकृत और विस्तृत रूप से सुसज्जित है।
- यह एक महत्वपूर्ण जैन केंद्र भी है।
 - इसमें महावीर को समर्पित एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर है, जो लक्कुंडी में सबसे बड़े और सबसे पुराने जैन मंदिरों में से एक है।
- प्राचीन शिलालेखों में लक्कुंडी को 'लोक्की गुंडी' कहा गया है।
- लक्कुंडी को वास्तुकला की वेसर शैली को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है - जो नागर शैली और द्रविड़ शैली की वास्तुकला का संयोजन है।



स्रोत: [The Hindu - Lakkundi Temples](#)

स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POP) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन

- भारत ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत 2021 में वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने वाले POP के रूप में सूचीबद्ध खतरनाक कीटनाशक **क्लोरपाइरीफोस** को शामिल किए जाने का विरोध किया है।

स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POP) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में -

- यह एक अंतराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को POP के हानिकारक प्रभावों से बचाना है।
- इसे 2001 में अपनाया गया था और 2004 में यह लागू हुई।

- भारत ने 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि की।
- भारत ने कन्वेंशन में POP के रूप में सूचीबद्ध अधिकांश कीटनाशकों के निर्माण, उपयोग और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इसमें रसायनों की सूची तीन अनुलग्नकों में दी गई है।
 - अनुलग्नक ए (उन्मूलन के लिए), अनुलग्नक बी और सी (प्रतिबंध)।
- **स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POP):**
 - POP खतरनाक रसायन हैं जो मानव स्वास्थ्य और ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं।
 - वे लम्बे समय तक अक्षुण्ण रहते हैं तथा पूरे पर्यावरण में व्यापक रूप से वितरित रहते हैं।
 - वे खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवित जीवों में एकत्रित होते हैं और बढ़ते हैं तथा मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए विषाक्त होते हैं।

स्रोत: [DTE - Stockholm on POPs](#)

हिंद-प्रशांत समुद्री डोमेन जागरूकता (IPMDA)

- भारत IPMDA के अंतर्गत समुद्री निगरानी उपकरण प्राप्त करेगा।

IPMDA क्या है?

- यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण पहल है।
- उद्देश्य:
 - हिंद महासागर में डार्क शिपिंग जैसी गतिविधियों पर वास्तविक समय की जानकारी विकसित करना और प्रसारित करना।
 - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों - प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) को एकीकृत करना।
- **लॉन्च:** टोक्यो में क्राइ नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान (2022) में
 - **क्राइ सदस्य:** अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान

डार्क शिपिंग -

- यह शब्द ऐसे जहाज के लिए प्रयुक्त होता है जो अपनी स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) के बंद होने के बावजूद परिचालन कर रहा हो, जिससे समुद्री अधिकारियों के लिए उसका पता लगाना कठिन हो जाता है।
- यह तस्करी, अवैध व्यापार, अवैध मछली पकड़ने आदि जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।

स्रोत: [The Hindu - IPMDA](#)

ऑरेंज अर्थव्यवस्था(Orange Economy)

- यह उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो धन और रोजगार पैदा करने के लिए रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाती हैं। इसे रचनात्मक अर्थव्यवस्था(creative economy) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक इंटरनेट-सुविधायुक्त अर्थव्यवस्था है जो कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को अपनी रचनाओं से राजस्व अर्जित करने की अनुमति देती है।
 - क्रिएटर इकोनॉमी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के उदाहरण - यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्पोर्टिफाई आदि।
- **रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई पहल:**
 - **रचनात्मक अर्थव्यवस्था कोष:** सरकार ने 1 बिलियन डॉलर के रचनात्मक अर्थव्यवस्था कोष की घोषणा की है।

- **नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड:** भारत में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के कार्य को मान्यता देने, नवाचार और ऑनलाइन रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए।

वेब्स शिखर सम्मेलन -

- वेब्स मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है, जो विशेष रूप से भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर केंद्रित है।

स्रोत: [The Hindu - Orange Economy](#)

थैलेट्स(Phthalates)

- एक हालिया अध्ययन के अनुसार, प्रतिदिन थैलेट्स के संपर्क में आने से दुनिया भर में हृदय रोग से 3.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है।

थैलेट्स के बारे में -

- थैलेट्स रसायनों का एक समूह है जिसका उपयोग आमतौर पर प्लास्टिक को लचीला, मुलायम और टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है।
- ये रंगहीन, गंधहीन, तैलीय तरल पदार्थ हैं जिन्हें **प्लास्टिसाइज़र** भी कहा जाता है।
- ये उन प्लास्टिक सतहों से स्थायी रूप से नहीं जुड़ते जिन पर इन्हें लगाया जाता है।
- वे कई रोजमर्रा की चीजों में पाए जाते हैं जैसे:
 - खाद्य कंटेनर, प्लास्टिक पैकेजिंग, विनाइल फर्श, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, घरेलू सामान आदि।
- प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाली थैलेट-संबंधी हृदय रोग से होने वाली मौतों की सूची में भारत शीर्ष पर है।

थैलेट्स से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम -

- हृदयवाहिनी रोग (हृदय आघात और स्ट्रोक सहित)
- हृदय धमनियों की सूजन
- मोटापा
- बांझपन और प्रजनन संबंधी समस्याएं
- हार्मोनल असंतुलन
- कैंसर

स्रोत: [DTE - Phthalates](#)

ALH ध्रुव

- एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव के भारतीय सेना और वायु सेना संस्करणों को परिचालन के लिए मंजूरी दे दी गई है।
- इससे पहले एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुई घातक दुर्घटना के कारण इन्हें उड़ान भरने से रोक दिया गया था।

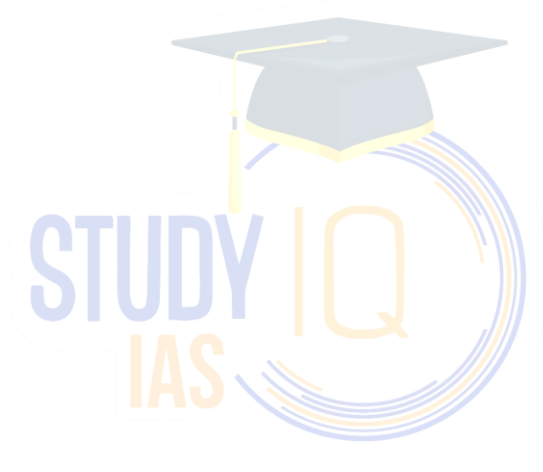
एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव के बारे में -

- यह सैन्य और नागरिक दोनों ऑपरेटरों के लिए एक बहु-भूमिका और बहु-मिशन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है।
- इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- ALH हेलिकॉप्टरों को भारतीय तटरक्षक बल के साथ-साथ सभी 3 भारतीय रक्षा बलों द्वारा संचालित किया जाता है।



- इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- इसे भारतीय सशस्त्र बलों में चेतक और चीता जैसे पुराने हेलीकॉप्टरों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

स्रोत: [The Hindu - Dhruv ALH](#)



संपादकीय सारांश

निजी सदस्य का विधेयक (Private Member's Bill - PMB)

संदर्भ

निजी सदस्य के विधेयक में भारत के विधायी परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध करने की अपार क्षमता है।

निजी सदस्य विधेयक (PMB) क्या है?

- निजी सदस्य विधेयक संसद में किसी सांसद (एमपी) द्वारा प्रस्तुत किया गया विधायी प्रस्ताव होता है, जो मंत्री नहीं होता है।
- इसमें सत्तारूढ़ दल (यदि कोई मंत्री न हो) और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल हैं।

निजी सदस्य के विधेयक का महत्व -

- **व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए मंच:** PMB सांसदों को, विशेष रूप से जो कार्यपालिका में नहीं हैं, मुद्दों को उठाने, कानून का प्रस्ताव करने और पार्टी लाइन से परे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है।
- **लोकतांत्रिक गहनता:** PMB विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंताओं पर बहस को प्रोत्साहित करके विचार-विमर्शपूर्ण लोकतंत्र को बढ़ाते हैं, जिन्हें अक्सर आधिकारिक कानून में नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- **नीतिगत नवाचार और सामाजिक जागरूकता:** PMB अपरंपरागत या उभरते मुद्दों को सामने लाते हैं - जैसे, डिस्कनेक्ट करने का अधिकार, ट्रांसजेंडर अधिकार - सार्वजनिक और संसदीय चर्चा की शुरुआत करते हैं।
- **अंतर-दलीय सहयोग:** PMB द्विदलीय सहभागिता को बढ़ावा देते हैं और कभी-कभी सामाजिक रूप से प्रासंगिक मामलों (जैसे, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रस्ताव) पर आम सहमति उत्पन्न करते हैं।
- **कार्यपालिका के प्रभुत्व पर अंकुश:** वे कार्यपालिका-विधायी शक्ति को संतुलित करने में मदद करते हैं, जिससे संसद विविध आवाजों के लिए एक मंच बनी रहती है, न कि केवल मंत्रिमंडल के लिए एक रबर स्टाम्प।
- **विधायी उद्भवन:** यदि पारित नहीं भी किया जाता है, तो भी PMB अक्सर बाद में सरकारी विधान को प्रभावित करते हैं (जैसे, आरटीआई अधिनियम, ट्रांसजेंडर अधिनियम), तथा नीति परीक्षण के रूप में कार्य करते हैं।

निजी सदस्यों के विधेयकों के समक्ष चुनौतियाँ -

- **कम सफलता दर:** स्वतंत्रता के बाद से अब तक केवल 14 PMB कानून बन पाए हैं। 1970 के बाद से कोई भी दोनों सदनों से पारित नहीं हुआ है।
- **समय का अपर्याप्त आवंटन:** केवल शुक्रवार का दिन ही आरक्षित है, और अक्सर सरकारी कामकाज, बजट चर्चा या व्यवधानों के कारण यह दिन भी नष्ट हो जाता है।
- **राजनीतिक प्राथमिकता का अभाव:** सत्तारूढ़ पार्टी आधिकारिक विधायी एजेंडे से भटकने के डर से PMB का समर्थन नहीं कर सकती है - यहां तक कि अपने सांसदों से भी नहीं।
- **व्यवधान और स्थगन:** सदन में बार-बार व्यवधान के कारण PMB पर अक्सर चर्चा नहीं हो पाती, जिससे वे प्रतीकात्मक कार्यवाही बनकर रह जाती हैं।
- **संस्थागत समर्थन नहीं:** PMB में अक्सर अनुसंधान और प्रारूपण समर्थन का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप खराब तरीके से तैयार किए गए प्रस्ताव संवैधानिक या कानूनी जांच का सामना नहीं कर पाते हैं।
- **दलबदल विरोधी प्रतिबंध:** दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) सांसदों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है, विशेष रूप से सत्ता पक्ष से, तथा उन्हें पार्टी लाइन से विचलित होने से हतोत्साहित करती है।

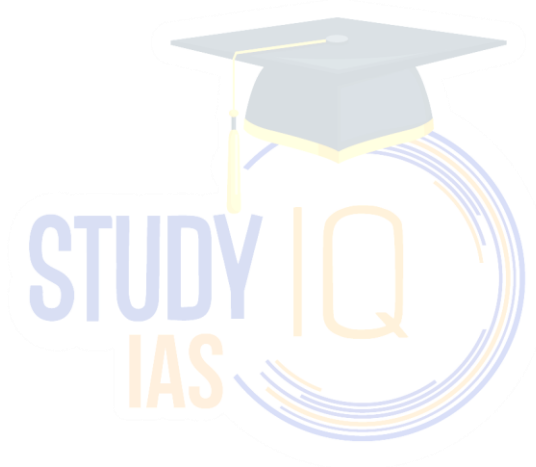
PMB तंत्र को मजबूत करने के लिए सुधार -

- **PMB के लिए समय की सुरक्षा:** PMB के लिए शुक्रवार के दिन की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय आपात स्थितियों को छोड़कर अन्य समय में इनका उल्लंघन न किया जाए।
- **PMB समीक्षा समिति का गठन:** एक समर्पित निकाय गुणवत्ता, संवैधानिकता और प्रासंगिकता के लिए PMB की जांच कर सकता है, और बहस के लिए प्राथमिकता सूची की सिफारिश कर सकता है।
- **उच्च प्रभाव वाले विधेयकों के लिए फास्ट-ट्रैक तंत्र:** द्विदलीय समर्थन या व्यापक सार्वजनिक हित वाले विधेयकों को, चाहे उनका मूल कहीं भी हो, शीघ्रता से पारित करने की अनुमति देना।
- **संसद के कार्य समय को बढ़ाना:** PMB के समय को बदलने के बजाय, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के सदस्यों के काम को समायोजित करने के लिए बैठक के समय को बढ़ाना।
- **'दस मिनट का नियम' (यूके मॉडल) लागू करना:** परिचय के समय PMB को संक्षिप्त भाषण देने की अनुमति दें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक विचारों पर कम से कम बहस हो या उन्हें रिकॉर्ड किया जाए, जिससे दृश्यता बढ़े।
- **सांसदों के लिए अनुसंधान सहायता को बढ़ावा देना:** सांसदों को ठोस कानून का मसौदा तैयार करने में मदद करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों और नीति शोधकर्ताओं तक पहुंच प्रदान करना, जिससे PMB की गुणवत्ता और गंभीरता में सुधार हो सके।

महत्वपूर्ण निजी सदस्य विधेयक और कुछ तथ्य				
क्र. सं.	विधेयक का नाम	वर्ष प्रारंभ	(एमपी) द्वारा प्रस्तुत	परिणाम/प्रभाव
1	हिंदू विवाह (संशोधन) विधेयक	1952	प्रभाकर कुंटे	हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में योगदान दिया
2	विधानमंडल की कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक	1956	फिरोज गांधी	कानून में पारित; विधायी कार्यवाही का संरक्षित प्रकाशन
3	सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक	1968	आनंद नारायण मुल्ला	कानून पारित; सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार
4	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	1967	दीवान चमन लाल	दहेज-संबंधी हिंसा पर बाद में बने कानूनों से प्रभावित
5	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक	2014	तिरुचि शिवा	2015 में राज्य सभा द्वारा पारित; 2019 के सरकारी कानून को प्रभावित किया
6	सूचना का अधिकार-संबंधी विधेयक	1990 के दशक (एकाधिक)	विभिन्न सांसद	आरटीआई अधिनियम, 2005 का मार्ग प्रशस्त किया

महत्वपूर्ण निजी सदस्य विधेयक और कुछ तथ्य				
7	महिला आरक्षण विधेयक	अनेक प्रयास	विभिन्न सांसद (जैसे, गीता मुखर्जी)	यद्यपि विधेयक पारित नहीं हुआ, लेकिन यह मुद्दा राजनीतिक सुर्खियों में बना रहा
तथ्य ★ स्वतंत्रता के बाद से अब तक केवल 14 PMB पारित हुए हैं और उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है और 1970 के बाद से कोई भी दोनों सदनों से पारित नहीं हुआ है। ★ 17वीं लोकसभा (2019-24) में, लोकसभा में 729 और राज्यसभा में 705 PMB पेश किए गए। ○ हालांकि, लोकसभा में केवल दो और राज्यसभा में 14 पर ही कभी चर्चा हुई। ★ 18वीं लोकसभा में अब तक केवल 20 सांसदों ने PMB पेश किए हैं। ★ 2024 के उद्घाटन और बजट सत्र के दौरान, लोकसभा में 64 PMB पेश किए गए, लेकिन एक पर भी चर्चा नहीं हुई।				

स्रोत: [The Hindu: Reviving a far-sighted but forgotten Bill mechanism](#)



चीन का रणनीतिक प्रयास - टैरिफ तनाव के बीच एशिया संबंध

संदर्भ

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के साथ बढ़ते आर्थिक तनाव के बीच, विशेष रूप से चीनी निर्यात पर 145% अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर, वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया की तीन देशों की यात्रा (14-18 अप्रैल, 2025) की। इस यात्रा का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के रणनीतिक और आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करना है।

यात्रा का महत्व -

आयाम	प्रमुख बिंदु
आर्थिक पुनर्संयोजन	यह दौरा दक्षिण-पूर्व एशिया में लचीले व्यापारिक संबंध बनाकर तथा वैकल्पिक विनिर्माण करके अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों का मुकाबला करने की चीन की रणनीति का हिस्सा है।
द्विपक्षीय समझौते	तीनों देशों के बीच एआई, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृषि और बुनियादी ढांचे (जैसे, कंबोडिया में फुनान टेको नहर) को कवर करने वाले 75 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी	यह अमेरिका के हस्तक्षेपवाद के विपरीत, गैर-हस्तक्षेप और आर्थिक साझेदारी पर आधारित चीन के नेतृत्व वाले मॉडल को बढ़ावा देता है।
क्षेत्रीय नेतृत्व	यह क्षेत्र में नियम-निर्धारक के रूप में चीन की भूमिका को मजबूत करता है, तथा BRI जैसी पहलों के माध्यम से दक्षिण चीन सागर आचार संहिता को आगे बढ़ाता है।
घरेलू राजनीतिक संदेश	इससे यह पता चलता है कि पश्चिमी दबाव और घरेलू आर्थिक चिंताओं के बावजूद चीन विश्व स्तर पर अलग-थलग नहीं है।

रणनीतिक निहितार्थ -

- **आसियान के लिए:** चीन बुनियादी ढांचे, व्यापार सुविधा और सुरक्षा वार्ता जैसे ठोस परिणाम प्रदान करता है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली हिंद-प्रशांत रणनीति से अधिक आकर्षक हो सकता है, जिसे अक्सर सुरक्षा-भारी माना जाता है।
- **अमेरिका के लिए:** यह यात्रा चीन से आर्थिक रूप से अलग होने और एकीकृत क्षेत्रीय रणनीति बनाने के अमेरिकी प्रयासों को जटिल बनाती है।
- **भू-राजनीतिक पुनर्संरक्षण:** दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ चीन की आर्थिक निर्भरता को बढ़ाता है, जिससे क्षेत्रीय राज्यों के लिए क्वाड और AUKUS जैसे अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधनों के साथ पूरी तरह से संरेखित होना कठिन हो जाता है।

निष्कर्ष -

शी जिनपिंग का दक्षिण-पूर्व एशिया दौरा आर्थिक शासन कला का लाभ उठाकर, मानक नेतृत्व प्रस्तुत करके, तथा क्षेत्रीय एकीकरण में अपनी केन्द्रीयता को सुदृढ़ करके हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को मजबूत करने की एक रणनीतिक चाल है - जो इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रधानता के लिए दीर्घकालिक चुनौती पेश कर रहा है।

स्रोत: [The Hindu: China's strategic push — Asia ties amid tariff tensions](#)